**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1206**

**27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: बढ़े हुए एमएसपी का प्रभाव**

**1206. श्री कनवर दीप सिंहः**

**क्या कृषि एवंकिसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः**

(क) क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञों नेतर्क दिया है कि एमएसपी की बढ़ोतरी मुद्रास्फीतिको बढ़ा देगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;और

(ग) इस स्थिति से बचने के लिए क्या-क्याउपाय किए गए हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): सरकार ने खरीफ फसलों 2018-19 के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत पर निर्धारित करने के अपने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की है जो 2018-19 के केंद्रीय बजट में किए गए वादे को पूरा करता है। प्राप्‍त सूचनाओं के अनुसार, उच्‍चतर एमएसपी के स्‍फीतिकारी प्रभाव के बारे में कुछ चिंताएं व्‍यक्‍त की गई हैं। यह आवश्‍यक नहीं है कि उच्‍चतर एमएसपी से बाजार मूल्‍य में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। मूल्‍य, अन्‍य बातों के अलावा, मांग और आपूर्ति स्‍थितियों पर निर्भर करता है।

 कुछ फसलों के थोक मूल्‍य एमएसपी से नीचे है जो लगातार दूसरे वर्ष बंपर उत्‍पादन दर्शाता है। किसानों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति दलहन जैसे उन फसलों के लिए उच्‍चतर एमएसपी के रूप में प्रोत्‍साहन के कारण है जिनमें पहले के वर्षो में उपभोक्‍ता मांग की तुलनामें अधिक कमी देखी गई थी जब खाद्य स्‍फीति दोहरे अंको में थी और समग्र स्‍फीति कम्‍फर्ट जोन से अधिक थी। कुछ राज्‍यों की कुछ मण्‍डियों में थोक मूल्‍यों के एमएसपी के नीचे रहने के मुद्दे के समाधान के लिए वर्ष 2017-18 हेतु तूर, मूंग और उड़द के लिए पीएसएस के तहत खरीद बढ़ाया गया है, और इसलिए भविष्‍य में मांगकी तुलना में आपूर्ति में कमी की आपात स्‍थितियों में मूल्‍य स्‍थिर करने के लिए पर्याप्‍त भण्‍डार है। इसके अलावा, अन्‍य वर्तमान समर्थन पहलों के साथ-साथ एक सुद्दढ़ खरीद तंत्र स्‍थापित करना और ग्रामीण कृषि बाजारों के पुनरूद्धार (जीआरएएम) जैसे बजट 2018-19 द्वारा इसी क्रम में घोषित उपायों की मदद से उपभोक्‍ता और उत्‍पादक मूल्‍यों के बीच अंतर को कम कियाजा सकेगा।

\*\*\*\*\*